परिवेश सुधार के लिए निर्मित अन्य स्थलों आदि के संरक्षण परिसंरक्षण मामलों के अध्ययन और सलाह देने के लिये दिल्ली नगर कला आयोग नामक संस्था बनाई गयी है । इसके साथ ही नगर प्राधिकरण के अतिरिक्त जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पार्कों/उद्यानों का विकास और अनुरक्षण करता है दिल्ली विकास प्राधिकरण का बागवानी विभाग भी अपने दायरे के हरे-भरे क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करता है और मास्टर प्लान के हरित क्षेत्र, निकटवर्ती पार्कों और जिला पार्कों का भी विकास करता है । प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले बाल उद्यान और खेल मैदान आदि का भी विकास करता है ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड दिल्ली के आस-पास के प्राथमिकता वाले शहरों का विकास करने का विचार रखता है । इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार/योजना बोर्ड द्वारा कई परियोजनायें प्रारम्भ की गई हैं । दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिये राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड ने एक विस्तृत निवेश कार्यक्रम तैयार किया है जिसके लिये बोर्ड के राज्य सेक्टर के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उनकी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एन० सी० आर० प्लानिंग बोर्ड के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गये हैं । बोर्ड ने प्राथमिकता शहरों और दिल्ली महानगर क्षेत्र शहरों से संलग्न नई बस्तियाँ बनाने का भी प्रस्ताव किया है ताकि दिल्ली में आबादी को सीमित किया जा सके और राजधानी क्षेत्र का संतुलित और सुनियोजित विकास किया जा सके । इससे दिल्ली में स्लमों की बढ़ोतरी को रोकने में भी मदद मिलेगी जो इस समय मूलतः बाहर से भारी संख्या में लोगों के कारण पैदा हो रही है ।

HUDCO loan to housing Agencies of Gujarat

1671. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that HUDCO loan to housing agencies of Gujarat is reducing year by year;

(b) the amount of loan which has been sanctioned and disbursed by the HUDCO to housing agencies of Gujarat during the last three years and the details thereof;

(c) what are the reasons for decreasing the HUDCO loan to housing agencies of Gujarat; and

(d) whether HUDCO propose to increase loan to housing agencies of Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) No, Sir. As may be seen from the figures given below the loan allocation to Gujarat from HUDCO has been increasing steadily.

HUDCO Loan Assistance to Gujarat

(Rs. in Crores)

Year	Allocation	Sanction	Release
1990—91	40.39	52.62	50.85
1991—92	43.32	43.55	29.16
1992—93	48.63	60.41	58.10

(c) and (d) Question does not arise in view of the above reply.

Allotment of flats under self Financing scheme by DDA

1672. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Development Authority has not allotted flats registered under the self financing schemes;

(b) the number of flats which have been allotted to the registrants in different self financing schemes uptil now;

(c) what are the reasons for the delay in allotment of flats under the self financing schemes; and

(d) by when the DDA is expected to clear the back-log registered under self financing schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir. According to the DDA under the self financing Scheme initially allocations are made after inviting applications from the registrants from time to time and on completion of the construction of the allocated flats, the specific flat nos. are allotted to the allocatees who have made the payment according to the given schedule.

(b) 61,100.

(c) The flats are offered to the registrants on finalisation of the plans by the Planning/ Engineering Wing of DDA. The last such